

आईआईटी की जमीन वन विभाग के नक्शे में दूटेंगे

भास्कर संवाददाता | इंदौर

आईआईटी को सिमरोल में आवंटित 502 एकड़ जमीन में आ रही करीब चार एकड़ की कमी को दूर करने के लिए अब वन विभाग से मदद मांगी गई है। आवंटित जमीन में से 200 एकड़ जमीन वन विभाग की ही है। कोशिश हो रही है कि कम पड़ रही चार एकड़ जमीन वन विभाग की जमीन में समायोजित हो जाए। इसके लिए बुधवार को वन विभाग के अधिकारियों के साथ अपर कलेक्टर व राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। तय हुआ कि अगले सप्ताह आईआईटी के लेआउट प्लान के साथ वन विभाग के नक्शे व राजस्व विभाग के नक्शे का मौके पर मिलान किया जाएगा।

आईआईटी ने प्रशासन को साफ कर दिया है कि वह आवंटित से कम जमीन नहीं लेगा, क्योंकि उनका मास्टर प्लान मंजूर हो चुका है। ऐसे में प्लान में बदलाव करना लंबी प्रक्रिया होगी। इसके बाद अपर कलेक्टर रवींद्रसिंह, एडीएम आलोकसिंह, वन विभाग के अधिकारी अभय जैन की कलेक्टोरेट में बैठक हुई। इसमें वन विभाग के नक्शे का राजस्व विभाग के नक्शे के साथ मिलान किया गया। ऊपरी मिलान में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर तय हुआ कि आईआईटी के प्लान के साथ वन विभाग व राजस्व विभाग के नक्शों का मौके पर मिलान कर लिया जाए। वन विभाग की जमीन पर यह चार एकड़ जमीन समायोजित हो जाने से प्रशासन को आईआईटी के लिए अतिरिक्त चार एकड़ की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपर कलेक्टर ने कहा कि अगले सप्ताह मौके पर सभी नक्शों का मिलान किया जाएगा और जरूरत हुई तो फिर सीमांकन किया जाएगा। उम्मीद है कि चार एकड़ जमीन की कमी का मसला दूर हो जाएगा।